मुख्यमंत्री भजनलाल वसुंधरा राजे से मिलने उनके निवास पर गये

दोनों नेताओं की 35 मिनट की मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है

- जानकार लोगों का मानना है कि भजनलाल और वसुंधरा राजे की मुलाकात में मुख्यतः विधानसभा के बजट सत्र तथा प्रदेश में चल रहे संगठन पर्व पर चर्चा हुई होगी।
- यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल व विस्तार तथा राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई हो सकती है।

जयपुर, 22 जनवरी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर चल रही सियासी चर्चा के बीच, बुधवार को राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाने वाली खबर सामने आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। दोनों के बीच हुई करीब 35 मिनट की मुलाकात ने राज्य में संभावित सियासी बदलावों और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को हवा दे दी है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में आगामी बजट 2025-26 और संगठन पर्व को लेकर चर्चा हुई।

ज्ञातव्य है कि 31 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और संभावना जताई जा रही है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में भजनलाल सरकार अपना बजट पेश कर सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल और वसुंधरा राजे के बीच की मुलाकात को लेकर भी यही माना जा रहा है कि आगामी बजट को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि प्रदेश में चल रहे संगठन पर्व को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा की गई।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उक्त दोनों की चर्चाओं के बीच इस समय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात काफी अहम हो जाती है, क्योंकि प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है। इसके साथ ही, सरकार को अब राजनीतिक नियुक्तियां भी करनी हैं। वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री चुकी हैं। ऐसे में भजनलाल शर्मा का पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से इन मुद्दों पर चर्चा करना संभव है। विश्लेषकों के अनुसार, पिछले दिनों जिस तरह से राजे की सक्रियता बढ़ी है और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां, प्रदेश भाजपा संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार में राजे की राय को भी महत्व दिया जा सकता है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी समन्वय बनाने के निर्देश दिए थे।

दरअसल, प्रदेश में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चा लगातार हो रही है। बीच में 24 जनवरी को मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन 24 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का सीकर मोदी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद राज्यपाल 24 जनवरी को कोटा के वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय और कोटा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे 25 जनवरी को सुबह 10 बजे आरआईसी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद उदयपुर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उनका जाना प्रस्तावित है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल विधानसभा बजट के बाद हो सकता है।

कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद मुस्कुराते हुए उनके आवास से रवाना हुए। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने सीधे अपने कार्यालय का रुख किया, जहां गोपालन और पशुपालन विभाग के साथ बजट पूर्व संवाद किया जा रहा था।

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना का नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री निवास पर इसके पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, सांसद मदन राठौड़ सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

रामजल सेतु लिंक परियोजना-मुख्यमंत्री ने नदियों को जोड़ने की योजना को नया नाम दिया

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगाँठ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोस्टर का भी विमोचन किया

- इस लिंक परियोजना में चंबल और उसकी सहायक नदियों कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध और मेज के सरप्लस वर्षा जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती व गंभीर नदी बेसिनों में भेजा जायेगा।
- इस परियोजना से सवा तीन करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ ढाई लाख हैक्टेयर नये क्षेत्र की सिंचाई तथा डेढ़ लाख हैक्टेयर में सिंचाई के लिये अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी।

जयपुर, 22 जनवरी। अयोध्या में रामजन्मभूमि पर भगवान श्रीराम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना का नामकरण "रामजल सेतु लिंक परियोजना" करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि गत 17 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में संशोधित पीकेसी परियोजना के एमओयू के अवसर पर पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों का जल रामसेतु जल संकल्प कलश में प्रवाहित किया गया था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर रामजल सेतु लिंक परियोजना के नामकरण के उपरान्त, इसके पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष आज के ही दिन 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्रीराम अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। भगवान श्रीराम ने सत्य की विजय के लिए समुद्र पर सेतु बनाकर एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का काम किया। उनसे प्रेरणा लेते हुए ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए नदियों को जोड़ने की यह महत्वाकांक्षी परियोजना लाई गई है।

उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के सपने को साकार करते हुए, रामसेतु जल परियोजना पूर्ण होने पर प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। इस लिंक परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियों, कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध और मेज के सरप्लस वर्षा जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, गंभीर नदी बेसिनों में भेजा जाएगा। इसमें लगभग सवा तीन करोड़ लोगों को पेयजल की उपलब्धता के साथ-साथ, लगभग ढाई लाख हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग डेढ़ लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही, इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों के विकास के लिए भी पानी मिल सकेगा।

इस दौरान, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, सांसद मदन राठौड़, विधायक बहादुर सिंह कोली, डॉ. शैलेष सिंह, डॉ. सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल सहित, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

ताहिर हुसैन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उल्लेख करना उचित होगा कि 10-15 दिन प्रचार करना (चुनाव जीतने के) प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं होता, चुनाव क्षेत्र की वर्षों तक सेवा की जाती है, ख़याल रखा जाता है। अगर याचिकाकर्ता जेल में होने के कारण, पिछले कुछ वर्षों में उस क्षेत्र की सेवा नहीं कर सका है, तो कोई कारण नहीं है कि उसे रिहा किया जाये।"

जस्टिस अमानुल्लाह ने आरोपों की गंभीरता को तो स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि इस समय तो वे केवल आरोप ही हैं।

जेल में गुजरी अवधि (5 वर्ष) के एक बहुत छोटे हिस्से के रुप में, तथा इस तथ्य के प्रकाश में, कि आरोपी को अन्य प्रकरणों में जमानत मिल चुकी है, उसे 4 फरवरी, 2024 तक अन्तरिम जमानत दी जा सकती है, लेकिन जमानत बीएनएसएस, 2023 की धारा 482 एवं 484 की शर्तों के तहत होगी। हुसैन प्रचार के दौरान, एफआईआर में दिये गये मुद्दों को नहीं उठायेंगे तथा वे 4 फरवरी, 2024 को दोपहर तक आत्मसमर्पण कर देंगे।

'ट्रेनी एसआई की फील्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

माथुर ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों की ओर से कथित रूप से अपनाए गए अनुचित साधनों के आधार पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। इन अभ्यर्थियों के खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है। ऐसे में ट्रायल पूरा होने के बाद ही यह तय होगा कि उन्होंने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया था या नहीं। अपील में यह भी कहा गया कि अपीलार्थियों पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। ऐसे में उन्हें सेवा में बने रहने का अधिकार है और केवल याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर उन्हें सेवा से नहीं हटाया जा सकता। एकलपीठ में इन तथ्यों पर ध्यान दिए बिना पूरी भर्ती पर ही यथास्थिति के आदेश दे दिए और फील्ड ट्रेनिंग भी रोक दी। अपील में यह भी कहा गया कि एसआईटी, महाधिवक्ता और कैबिनेट सब कमेटी की राय सिर्फ सुझावात्मक है और राज्य सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 18 नवंबर को भर्ती में यथा-स्थिति के आदेश दिए थे। वहीं गत सुनवाई पर फील्ड ट्रेनिंग पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने फील्ड ट्रेनिंग पर गए ट्रेनी उपनिरीक्षकों को वापस बुला लिया था।

कोटा में एक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। छात्र ने क्यों आत्महत्या की, इसके कारण पता नहीं चले हैं। लेकिन 24 जनवरी को उसका जेईई मेन्स का एग्ज़ाम था।

गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं की झांकी दिखेगी

- झांकी की थीम सशस्त्र बलों में एकजुटता व एकीकरण के वैचारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेगी।

नयी दिल्ली, 22 जनवरी। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एकजुटता और एकीकरण की भावना को प्रदर्शित करते हुए, पहली बार तीनों सेनाओं की झांकी कत्तर्व्य पथ पर दिखाई देगी। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि 'सशक्त और सुरक्षित भारत' थीम के साथ यह झांकी सशस्त्र बलों में एकजुटता और एकीकरण के वैचारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और परिचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित होगी।

झांकी में तीनों सेनाओं के बीच नेटवर्किंग और संचार की सुविधा प्रदान करने वाले एक संयुक्त संचालन कक्ष को दर्शाया जाएगा। यह स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन , तेजस मार्क - दो लड़ाकू विमान, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, विध्वंसक युद्धपोत विशाखापत्तनम और एक रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट के साथ जमीन, पानी और हवा में समन्वित ऑपरेशन का प्रदर्शन करते हुए युद्ध के मैदान का परिदृश्य प्रस्तुत करेगी। यह बहु-डोमेन संचालन में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को दर्शाता है। ये मंच रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के विजन का उदाहरण है।

रक्षा मंत्रालय में इस वर्ष को 'सुधारों का वर्ष' घोषित किया गया है। सैन्य मामलों के विभाग के मूल में संयुक्तता और एकीकरण हैं। इन्हें समकालीन और भविष्य के संघर्षों में सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता को अधिकतम करने की दिशा में प्रमुख निर्माण खंडों के रूप में पहचाना जाता है।

पाँचवीं की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहुंच कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पूर्व की रंजिश होने के चलते उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

22 राज्यों ने राष्ट्रपति ट्रम्प के "बर्थ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है। सन् 1868 में हुए 14 वें संशोधन के अनुसार अमेरिका में जन्मे हर बच्चे को अमेरिकन नागरिक माना जाता है।

यह संशोधन कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रुप से बसे सभी लोग उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन अमेरिका व उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं।

डॉनल्ड ट्रम्प के आदेश में अमेरिका में जन्मे बच्चों के माता -पिता अगर कानूनन अमेरिकन नागरिक नहीं हैं तो उस बच्चे को अमेरिका में जन्म लेने मात्र से अमेरिकन नागरिकता नहीं मिल जाएगी। आदेश कहता है कि उन बच्चों को भी अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी जिनकी मां कानूनन अमेरिका में है पर अस्थायी रुप से, जैसे वह छात्र वीसा या पर्यटन वीसा पर अमेरिका में है और जिनके पिता अमेरिका के नागरिक नहीं है या कानून स्थायी निवासी नहीं है।

ट्रम्प का कहना था कि दूसरे देश की महिलाएं बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आती हैं ताकि उनके बच्चों को अमेरिकन नागरिकता मिल जाए।

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुमान के अनुसार अमेरिका में जनवरी 2022 में 11 मिलियन अवैध इम्मिग्रैंट्स थे। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह संख्या अब बढ़कर 13 से 14 मिलियन के बीच हो गई होगी। उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को अमेरिकन नागरिकता प्राप्त है।

नागरिकता छिनने से इन लोगों को कई सरकारी कार्यक्रमों जैसे मैडिकैड हैल्थ इंश्योरैंस, (जो बुढापे में मिलता है) नौकरी मिलना और मतदान आदि।

कानूनविदों के अनुसार जन्म पर आधारित नागरिकता एक कार्यकारी आदेश से खत्म नहीं की जा सकती है इस पर मुकदमा हो सकता है।

एक संवैधानिक विशेषज्ञ तथा युनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया लॉ स्कूल के प्रोफेसर साई कृष्णा प्रकाश का कहना है कि वे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे पर इसका फैसला अदालत करेगी। एक व्यक्ति इसका फैसला नहीं कर सकता है।"

प्रकाश ने कहा कि ट्रम्प फैडरल एजेंसी के कर्मचारियों की नागरिकता की व्याख्या बहुत ही सीमित आधार पर करवा सकते हैं। पर जिसे भी नागरिकता से इन्कार किया जाएगा वह अदालत में इसे चुनौती देगा, इससे लम्बी कानूनी व लड़ाइयां शुरु हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इसी में उलझ जाएगा।

जन्म आधारित नागरिकता के अधिकार को संविधान संशोधन से ही खत्म किया/ जा सकता है पर इसके लिए हाउस ऑफ रिप्रैजैन्टेटिटस और सीनेट में दो तिहाई बहुमत की जरुरत होगी तथा तीन चौथाई राज्यों के समर्थन की भी जरुरत होगी। रिपब्लिकन के सीनेट में 53 सदस्य है और डैमोक्रेटिक के 45 तथा 2 निर्दलीय सदस्य है। हाउस ऑफ रिप्रैजैन्टेटिटस में रिपब्लिकन पार्टी के 218 सदस्य है और डैमोक्रेटिक पार्टी के 215 तथा दो पद रिक्त है। इस प्रकार कांग्रेस के ट्रम्प के पास आवश्यक बहुमत नहीं है।

चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा की याचिका पेश

- गत वर्ष अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था।

नई दिल्ली, 22 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल 15 फरवरी को भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दायर हुई एक समीक्षा याचिका में कोर्ट के दो अगस्त 2024 के उस आदेश पर विचार की मांग की गई है, जिसके तहत कोर्ट ने 2018 की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों द्वारा एकत्रित 16,518 करोड़ रुपये को जब्त करने की मांग को नकार दिया था।

समीक्षा याचिका में दो अगस्त 2024 के उक्त आदेश को वापस लेने की मांग की गई है तथा उस पिछली याचिका को बहाल करने की मांग की गई है, जिसे कोर्ट ने 2 अगस्त को उक्त आदेश देते समय खारिज कर दिया था। उक्त याचिका में चुनावी बॉण्ड से एकत्रित धन राशि को जब्त करने की मांग की गई थी। यह याचिका खेमसिंह भाटी ने दायर की थी।

समीक्षा याचिका में कहा गया है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) मामले में फैसले ने चुनावी बॉण्ड योजना को शुरुआत से ही अमान्य मान लिया है। इसी वजह से राजनीतिक दलों द्वारा एकत्र की गई राशि को जब्त करने की मांग करने वाली बाद की याचिकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता था। याचिका में आगे कहा गया कि चुनावी बॉण्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त राशि को जब्त करने की मांग वाली याचिकाओं को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खारिज करना अप्रत्यक्ष रूप से एडीआर फैसले को संशोधित करता है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल 15 फरवरी को भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। अदालत के फैसले के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ डेटा साझा किया। चुनाव आयोग ने इस डेटा को सार्वजनिक कर दिया।

प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रामलला के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ी

- मंदिरों में एक किलोमीटर लम्बी लाइनें लगी।

अयोध्या, 22 जनवरी। अयोध्या में भव्य राममंदिर में श्रीरामलला की पहली वर्षगांठ के मौके पर उनके दर्शन पूजन के लिये भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। घने कोहरे और ठंड के बीच बुधवार भोर से ही कतारबद्ध हुये रामभक्तों ने अपने आराध्य का दर्शन-पूजन किये। मंदिर के चारों ओर जय श्रीराम के जयकारे लगते रहे।

भव्य मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हुए थे। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक बुधवार को राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर श्रद्धालुओं का रेला नजर आया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि हिंदू कैलेण्डर के अनुसार 11 जनवरी को ही पहली वर्षगांठ मनाई जा चुकी है तीन दिन आयोजन भी हुए। उस समय भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किये थे।

राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर हनुमानगढ़ ी में दर्शन के लिए एक किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। इसके अलावा दशरथ महल-कनक भवन सहित अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उधर, मणिरामदास छावनी में सुबह रथयात्रा के बाद 41 दिवसीय अनुष्ठान का आगाज हो गया। इसमें सवा लाख से भी अधिक श्रीराम रक्षा स्रोत का जाप होगा।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई 30 जनवरी को

सुलतानपुर, 22 जनवरी। सुलतानपुर में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते एक बार फिर सुनवाई टली गयी। सुलतानपुर एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में 30 जनवरी को जिरह पूर्ण करने के लिए सुनवाई की तिथि नियत की है।

ट्रम्प के महत्वाकांक्षी, नारेबाजी पूर्ण भाषण के बाद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह भी बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ैलेन्स्की संकट को हल करने और युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर काम करने के लिए तैयार हैं। तथापि, पुतिन समझौता वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। संभवतः ट्रम्प को यह भनक लग गई होगी कि पुतिन ट्रम्प की धमकियों के आगे आसानी से नहीं झुकेंगे।

ट्रम्प ने यहाँ तक कहा है कि इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को नए हथियारों की आपूर्ति करेगा। उन्होंने यूक्रेन की वर्तमान कठिनाई के प्रति सहानुभूति जताई। यूक्रेन एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में है, जो रूस द्वारा निरंतर की जा रही बमबारी और मिसाइल हमलों से ज्यादा सुरक्षा प्रदान नहीं करती।

ट्रम्प ने कहा, "यूक्रेन एक मैदानी इलाके वाला देश है और कृषि के लिए बहुत अच्छा है तथा एक समय में यह दुनिया के बाज़ार में अनाज का एक प्रमुख सप्लायर था।" रूस के हवाई हमले बड़े-बड़े भवनों को धराशायी कर रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोग मर रहे हैं। ट्रम्प ने अफसोस जताया कि यह युद्ध युवा लोगों की मौत का कारण बन रहा है। ऐसा लगता है कि अब यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस के प्रति अमेरिका का रवैया और अधिक सख्त होगा, रूसी हमलों का सामना करने के लिए यूक्रेन में और अधिक शक्तिशाली हथियार और युद्ध प्रणालियाँ भेजी जाएंगी।

इस संदर्भ में, ट्रम्प की रूस के आंतरिक स्थिति के बारे में की गईं टिप्पणियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। ट्रम्प ने कहा कि वे मानते हैं कि रूस "एक बहुत बुरी स्थिति में है।" रूस की अर्थव्यवस्था संकट में है और वहाँ कीमतें बढ़ रही हैं। युद्ध के और बढ़ने से देश में तबाही मच सकती है और व्यापक जन आक्रोश पैदा हो सकता है।

शायद, यूक्रेन संकट को सुलझाने में अपनी व्यक्तिगत असमर्थता को समझते हुए, ट्रम्प अब रूस और पुतिन के प्रति अधिक शत्रुतापूर्ण रुख अपना रहे हैं। चीन में भी वे निवेश बढ़ा रहे हैं, साथ ही चीन के राष्ट्रपति से इस संकट को हल करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध कर रहे हैं।

आखिरकार, चीन, यूक्रेन संकट में फंसे रूस को बाहर निकलने में मदद कर रहा है। भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद कर और महत्वपूर्ण आपूर्ति भेजकर, चीन ने रूस की युद्ध गतिविधियों में मदद की है। ट्रम्प उम्मीद करते हैं कि दबाव में आकर शायद चीन रूस को यूक्रेन युद्ध जल्दी समाप्त करने के लिए समझाने में सक्षम होगा।

दूसरी तरफ, चीन को अपनी आतंरिक आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जहाँ समग्र आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है। चीन के उत्पादों पर कर बढ़ाने की ट्रम्प की धमकी से आर्थिक स्थिरता और भी बिगड़ सकती है। यदि चीन अमेरिकी मांगों के प्रति सहमत नहीं होता है, तो उसे अपने देश में गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है।

इस वैश्विक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीन एशियाई शक्तियों, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के ढांचे के तहत एक नया प्रयास शुरु किया है। क्वाड एक आर्थिक और रणनीतिक संगठन था, जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया में चीन के विस्तारवाद का विरोध था।

ट्रम्प के नए विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जो चीन के प्रति अपने कठोर रुख के लिए भी प्रसिद्ध हैं, ने उद्घाटन के लगभग तुरंत बाद अपनी पहली कूटनीतिक पहल की। जब ट्रम्प वाइट हाउस में अपना कार्यभार संभाल रहे थे, मार्को रुबियो चार क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ प्रारंभिक सत्र आयोजित कर रहे थे।

इन चार विदेश मंत्रियों को वॉशिंगटन में विशेष अहमियत दी गई और उन्हें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भविष्य की व्यवस्था पर औपचारिक चर्चाओं में शामिल किया गया।

वैश्विक कूटनीतिक संकट की इस स्थिति में, भारत को एक बहुत ही जटिल भूमिका निभानी होगी और अपने राष्ट्रीय हितों को तवज्जो देनी होगी। भारत के लिए सबसे कठिन परीक्षा तब होगी, जब उसे चीन से सीमाओं पर सीधे खतरे का सामना करना पड़ेगा और चीन की "सलामी स्लाइसिंग" नीति का सामना करना होगा, जो उच्च हिमालयी सीमाओं पर लागू हो रही है।

इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए अपनी स्वयं की ताकत होनी चाहिए, ताकि ऐसे हालात को अपनी शर्तों पर नियंत्रित किया जा सके। भारत को इस उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए।

ट्रक टिपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फल विक्रेता, सावनूर से चले थे और फल बेचने के लिए यालापुरा मेले की ओर जा रहे थे। उत्तर कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक एम नारायण ने कहा कि ये सावनूर-हुबली रोड पर यात्रा कर रहे थे, ये दुर्घटना जंगली इलाके में हुई है।

नारायण ने मीडिया को बताया, सुबह लगभग 4 बजे, ट्रक चालक दूसरे वाहन को साइड देने के चक्कर में एकदम बायीं ओर चला गया और लगभग 50 मीटर गहरी घाटी में गिर गया। उन्होंने कहा कि घाटी में सड़क पर कोई सुरक्षा दीवार नहीं है। अधिकारी ने कहा, कुछ की मौके पर ही मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हुबली के केआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दुर्घटना पर दुख जताया है। सिद्धारमैया ने कहा- मैं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इन दुखद घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। मृतकों के परिवारों को सरकार मुआवजा देगी।

आग लगने की अफवाह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि "हमारी प्रारंभिक जानकारी यह है कि पुष्पक एक्सप्रेस के एक कोच के अंदर हॉट एक्सल या ब्रेक-बाइंडिंग (जैमिंग) के कारण चिंगारी उठी और कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने चेन खींच दी और उनमें से कुछ ट्रेन से नीचे कूद गए और उसी समय, कर्नाटक एक्सप्रेस बगल के ट्रैक से गुजर रही थी, जो यात्रियों को कुचलती हुई गुजर गई।

जलगांव से अनेक यात्री ट्रेन पर चढ़े थे और हादसे वाली जगह पर चेन खींच कर उतरे और रॉन्ग साइड से ट्रैक पार करने की कोशिश की। जो लोग विपरीत दिशा में की ट्रैक पर खड़े थे, या पार करने की कोशिश कर रहे थे, वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई।

हादसे की भयावह तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। घटना के बाद रेलवे के कई अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जलगांव सिविल हॉस्पिटल के डीन के अनुसार, 12 डेड बॉडी अस्पताल में लाई गईं हैं और 40 घायलों को भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद, गांव के लोगों ने घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया है। साथ ही स्थानीय थाने के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि राहत-बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहां के लोगों ने निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। लखनऊ जंक्शन स्टेशन एनईआर पर हेल्पलाइन नंबर (8957409292) स्थापित किया गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालयः** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालयः** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालयः** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908